www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 34 | जौनपुर, शनिवार, 19 सितम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

2000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बीच वोटों की गिनती शुरू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह आठ बजे शुरू होने के बीच विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के 2,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। मतों की गिनती जारी रहने के मद्देनजर प्रमुख सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित की गई है और मतगणना केंद्र के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार केंद्रीय पदों के लिए मतगणना 'नॉर्थ कैंपस' स्थित विश्वविद्यालय खेल स्टेडियम के बहुउद्देश्यीय हॉल में हो रही है। डूसू चुनाव के नतीजों से यह संकेत मिलेगा कि किस छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रुख और उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मतगणना और नतीजों की घोषणा शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्र और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और परिसरों में पैदल गश्ती दल, मोटरसाइकिल दस्ते और पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) के वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रमुख स्थानों पर अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ।

ठाणे में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर कार्रवाई

ठाणे , (एजेंसी)। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप को कथित रूप से अवैध तरीके से रखने और बेचने के आरोप में 35 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलती है। एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भोईवाड़ा पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के नरपोली निवासी अकबर आदम शाह को पकड़ा। उसके पास से 100 मिलीलीटर की कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड युक्त एएनआरईएक्स कफ सिरप की 119 बोतलों से भरा एक बोरा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी से 24,990 रुपये मूल्य का कफ सिरप जब्त किया गया। आरोपी बिना किसी वैध चिकित्सीय पर्ची या कानूनी अनुमति के इस पदार्थ का वितरण कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और स्वापक औषधि एवं मनरूप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन में तेजी से आगे बढ़ता भारत, ये नए युग की शुरुआत : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को भारत की पर्यावरण से जुड़ी उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, "अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है।" उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत की विंड एनर्जी क्षमता में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। हाइड्रो–एनर्जी क्षमता में भी मजबूत वृद्धि देखी गई है। नया भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी फोकस कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार इन क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी रास्ते खोल रही है। इन प्रयासों से भारत की नॉन–फॉसिल एनर्जी क्षमता में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ई–मोबिलिटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत में हर साल केवल 3,000 ई–व्हीकल बिकते थे। पिछले साल करीब 25 लाख ईवी की बिक्री हुई, जो एक अविश्वसनीय वृद्धि है। इससे पर्यावरण को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि फास्टैग से टोल बूथ पर इंतजार का समय और ईंधन की बर्बादी काफी कम हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि 2014 तक देश के सिर्फ 5 शहरों में 250 किमी से कम मेट्रो नेटवर्क था। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1 हजार किमी से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण से करोड़ों लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे पर्यावरण को भी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा विकास तेज भी है और सस्टेनेबल भी है। आज जल संरक्षण में भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं।'

केंद्र सरकार ने 14 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 7 नामों पर लगी मुहर

नई दिल्ली, (एजेंसी)।केंद्र सरकार ने शनिवार को अलग–अलग हाई कोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जजों की सूची जारी करते हुए लिखा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।" दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 7 जजों की नियुक्ति की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज नियुक्त किया गया है। वहीं, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। अरुण भारद्वाज अभी दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। इससे पहले, 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए 8 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश भेजी थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उनमें से सिर्फ 7 नामों को मंजूरी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है। फिलहाल वहां 44 जज काम कर रहे हैं, यानी 16 पद खाली हैं। झारखंड हाई कोर्ट में तीन नए जज नियुक्त किए गए हैं, जिनमें मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा शामिल हैं।

खराब स्वास्थ्य के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए शाह, अस्पताल के उद्घाटन में नहीं पहुंचे

बंगलूरू, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य कारणों के चलते शनिवार को कर्नाटक के हुब्बल्ली में आयोजित एक निर्धारित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। अमित शाह को हुब्बल्ली के गब्बूर में केएलई जगद्गुरु गंगाधर महास्वामीगलु मूरुसाविरमठ मेडिकल कॉलेज के नए शैक्षणिक भवन और 1,200 बिस्तरों वाले केएलई अस्पताल व मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करना था। केएलई सोसायटी के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभाकर कोरे ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया कि डॉक्टरों की सलाह के बाद गृह मंत्री होटल में ही आराम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने खुद उन्हें यह संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कहा था। गृह मंत्री की अनुपस्थिति में इस संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बेलगावी के सांसद जगदीश शेट्टार और श्री जगद्गुरु मूरुसाविरमठ के श्री गुरुसिद्ध राजयोगेंद्र स्वामी ने मिलकर किया। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार देर रात हुब्बल्ली पहुंचे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें शनिवार को बाद में बेलगावी जिले में श्री बीरेश्वर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नए मुख्यालय भवन का भी उद्घाटन करना है।

अब सिस्टम डिजाइन और सटीक विनिर्माण के विस्तार पर ध्यान – अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान एक चर्चा में सेमीकंडक्टर स्किलिंग पर कहा कि भारत ने शुरू में 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा था और चार साल के अंदर ही लगभग 70,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के संस्थानों समेत लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को इंडस्ट्री–ग्रेड ईडीए टूल्स मिल रहे हैं। छात्रों को अपने डिजाइन को टेप–आउट तक ले जाने और अपने आइडिया को उत्पाद के रूप में विकसित होते देखने के मौके भी मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आईएसएम 2.0 के तहत, स्किलिंग पर फोकस चिप डिजाइन से आगे बढ़कर सिस्टम डिजाइन की ओर जाएगा, जिसका मकसद ऐसी प्रतिभा तैयार करना है, जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मांग हो। उन्होंने यह भी कहा कि क्लीनरूम टेक्नीशियन और मेंटेनेंस कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है और उद्योग जगत की मांग को देखते हुए आईएसएम 2.0 के तहत एक लाख टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। कल शुक्रवार को सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान एक चर्चा में वैष्णव ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन अब बुनियादी ढांचा तैयार करने के चरण से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर उद्योग बनाने की ओर बढ़ गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 के तहत अगला चरण एक पूरा सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित होगा। सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान एक चर्चा में श्री वैष्णव ने कहा कि आईएसएम 1.0 का फोकस बुनियादी इकोसिस्टम बनाने पर था, जबकि आईएसएम2.0 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को छह मुख्य स्तंभों दृ डिजाइन, मटीरियल और मशीनें, और अधिक फैब्स, और अधिक एटीएमपी यूनिट्स, अनुसंधान एवं विकास और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ाएगा।

भेदभाव न करना ही भारत की धर्म निरपेक्षता की असली परंपरा - मोहन भागवत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करने की उसकी ऐतिहासिक परंपरा में निहित है। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि मानव अहंकार और दंभ इस गलत धारणा को जन्म देते हैं कि कोई भी प्राकृतिक व्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है। उज्जैन में युवा धर्म संसद में करीब 1,700 जेन–जी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म के बारे में भारत की समझ पश्चिमी देशों की धर्म की धारणा से मौलिक रूप से भिन्न है, जो शासकों और धार्मिक सत्ताओं के बीच ऐतिहासिक संघर्षों से उपजी थी। उन्होंने कहा, हमारा देश हमेशा आपस में घुलमिल कर रहा है। यह अपने लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह हमारे लिए पंथ निरपेक्षता का यही अर्थ है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जहां पंथ (रिलिजन) बांधता है, वहीं धर्म मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। मानवीय दंभ के प्रति चेतावनी देते हुए भागवत ने कहा कि एक व्यक्ति का अहंकार अक्सर पूर्ण नियंत्रण का एक मिथ्या भ्रम पैदा करता है। भागवत ने कहा, उदाहरण के लिए, सूर्य को लें। उसका उदय और अस्त होना निश्चित है। मनुष्य अपने अहंकार में रहता है कि सब कुछ उसके अपने अधिकार से चलता है। और उसके कारण, वह यह गलत धारणा रखता है कि ऐसी चीजें भी उसकी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस बयान पर तंज करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या वह किसी कथित नॉन बायलॉजिकल की बात कर रहे हैं जिनका अवतरण दिवस अभी मनाया गया था? दिल्ली के जंतर–मंतर पर नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर छात्रों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद से आरएसएस ने जेन–जी तक अपनी पहुंच।

गुनां में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट न देने की चेतावनी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के गुना में, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है, एक तनावपूर्ण स्थिति तब पैदा हुई जब स्थानीय लोगों ने सड़क की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर उनके काफिले को रोक दिया। इस दौरान एक निवासी ने चेतावनी दी कि सड़क न होने का खामियाजा उन्हें वोट के नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है। सख्त लहजे में सिंधिया ने चेतावनी देने के इस तरीके पर आपत्ति जताई और लोगों से कहा कि वे इसके बजाय अनुरोध करें और काम पूरा कराने की जिम्मेदारी उन पर छोड़ दें। गुना के निवासी एक सड़क की हालत और उसके निर्माण को लेकर विरोध कर रहे थे। हाथों में पोस्टर लिए और षेड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने सिंधिया के काफिले को तब रोक लिया जब वे एक गाँव जा रहे थे। इस घटना का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक निवासी को सिंधिया से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह गुजारिश है कि इस बार यह सड़क बन जानी चाहिए। नहीं तो, जब आप वोटिंग के समय आएंगे, तो हम बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। सिंधिया ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए उस निवासी से कहा कि मेरे साथ कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करना।

दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दिल्ली में नाबालिग बच्ची के कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को लेकर देश में महिला सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में एक 17 साल की बच्ची के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। इसके बाद उसे बर्बरता से मार डाला गया। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि कुछ ही दिनों पहले एक और नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महिला सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। महिलाओं के विकास की सिर्फ खोखली बातें की जाती हैं। सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा होती है। अपराधी पर ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। कई मामलों में तो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं होती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि समाज और सरकार दोनों ही महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस स्थिति को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। यह दर्शाता है कि महिला सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया ।

सीएम के कार्यक्रम के बाद भी राजकीय इंटर कॉलेज में पसरी अव्यवस्था

जीआईसी प्रधानाचार्य के पत्राचार के बावजूद नही हो रही सफाई

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या ।राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में 8 सितम्बर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के सम्मान समारोह के बाद कॉलेज परिसर में अव्यवस्था का आलम है। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ के बाद परिसर में जगह–जगह कूड़ा, बालू और ईंटें बिखरी पड़ी हैं। बीतने के बावजूद सफाई नहीं होने से कॉलेज परिसर की सूरत बिगड़ी हुई है ।कार्यक्रम समाप्त होने के बाद परिसर को साफ–सुथरा कराकर पूर्व की स्थिति में लाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की थी ।इसके बावजूद अब तक इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। परिसर में बिखरी निर्माण सामग्री और कूड़ा विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है ।मामले को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने संबंधित विभाग को पत्राचार कर परिसर की सफाई एवं व्यवस्था दुरुस्त कराने का अनुरोध भी किया है। बावजूद इसके स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है ।आयोजित कार्यक्रम के बाद सरकारी शिक्षण संस्थान के परिसर में इस तरह की अव्यवस्था जिम्मेदार विभागों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है ।कॉलेज प्रशासन की ओर से पत्राचार के बाद भी यदि सफाई नहीं हो पा रही है तो सवाल यह है कि आखिर परिसर की सफाई और व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा?

संपादकीय

ब्रिक्स का कितना असर

ईरान पर अमेरिका और इजरायल की तरफ से छेड़ा गया युद्ध, होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग पर वर्चस्व की जंग, फिलीस्तीन पर इजरायल के हमले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थोपे टैरिफ से दुनिया भर के कारोबार में उथल–पुथल मची। तेल और गैस की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी से दुनिया में एक और मंदी का संकट गहराने लगा तो वहीं कई देशों के एक या दूसरे युद्ध में उलझने या किसी भी तरह उससे प्रभावित होने के कारण वैश्विक शांति भी प्रभावित हुई। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भारत में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ। ब्रिक्स 2006 में जब बना तो यह ब्रिक (बीआरआईसी) हुआ करता था, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया(भारत) और चीन शामिल थे, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका (द. अफ्रीका) इसमें शामिल हुआ और यह ब्रिक्स बना। अब इस समूह में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। सदस्य देशों के अलावा अबू धाबी, मलेशिया, बेलारूस, क्यूबा, कजाकिस्तान, बहरीन, वियतनाम, बुरुंडी, नाइजीरिया, युगांडा, उरुग्वे के प्रतिनिधि बैठक में मेहमान देशों के तौर पर शामिल हुए।संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ–साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में शिरकत की। यानी भारत के ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया की तकघ्रीबन आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता एक ही मंच पर इकठ्ठे हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण किरदार भी यहीं नजर आए। इस लिहाज से भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 काफी खास हो जाता है। क्योंकि इस शिखर सम्मेलन से यह संदेश निकला है कि दुनिया में किसी एक देश, किसी एक ताकतवर नेता की मर्जी हमेशा नहीं चल सकती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और कूटनीति परस्पर सम्मान और बराबरी के व्यवहार से ही निभाए जाते हैं। भारत के लिए यह सम्मेलन इसलिए अहम रहा क्योंकि पिछले कुछ बरसों में हमारी विदेश नीति में स्पष्ट नजरिए की कमी देखी गई है। गुट निरपेक्षता को दरकिनार करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि हम बार–बार अमेरिका के साए में दिखाई दिए, जिससे हमारे पारंपरिक मित्र देश भी थोड़े खिन्न नजर आए। गनीमत यह रही कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण संबंधों की प्राचीन ऊष्मा फिर झलकने लगी हैइस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान का भारत आना खास चर्चा में रहा।

ब्रिक्स – ग्लोबल साउथ की गूंज मजबूत

भाषा सिंहइतिहास ब्रिक्स देशों ने सम्मेलन में आर्थिक– सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों के साथ युद्ध, टैरिफ वार और प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों पर बेहतर समझदारी विकसित की। बुनियादी तौर पर सहमति बनी कि ब्रिक्स देशों को एक–दूसरे पर आने वाले संकटों में साथ देना चाहिए। ब्रिक्स में बड़ी आर्थिक ताकत बनने का दम–खम है और सम्मेलन में उसका रोडमैप सामने आया। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की गूंज क्या वर्ल्ड ऑर्डर में किसी बड़ी तब्दीली का संकेत दे रही है। सम्मेलन शुरू होने से पहले ही यह माना जा रहा था कि 11 सदस्य देश आपसी साझेदारी–व्यापार–अनुसंधान आदि पर सहमति तक पहुंचेंगे और अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने से बचेंगे। लेकिन ब्रिक्स के देश इससे आगे युद्ध और अमेरिका के टैरिफ वार के खिलाफ कड़ा संदेश देने में सफल रहे।इस सम्मेलन में भारत, चीन, रूस और ईरान ने युद्ध और बढ़ते भू–राजनीतिक दबाव से दुनिया भर में आम लोगों का जीवन तबाह होने और सप्लाई चेन बाधित होने की बात कही। भारत ने मौजूदा वैश्विक संकट की नब्ज पर हाथ रखते हुए क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार बनाए जाने पर चिंता जताई साथ ही आगाह किया कि दुनिया का कोई संकट एक क्षेत्र में नहीं रहता, यानी उसकी मार सब पर पड़ती है। यह सबका भुगता हुआ सच है, चाहे वह रूस–यूक्रेन संघर्ष हो या फिर ईरान पर अमेरिका का हमलाकृदुनिया के हर देश ने इनके असर को झेला है। यही वजह है कि ब्रिक्स 2026 के घोषणापत्र में तनावों और युद्ध जैसी स्थितियों को परस्पर संवाद से सुलझाने की बात पर जोर दिया गया है।ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबु धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद की ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई अलग बैठक भी बहुत चर्चा में रही। पश्चिम एशिया में गहरे तनाव के बीच दोनों नेताओं का एक मंच पर मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण था। दोनों ने तनाव घटाने, क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की कोशिशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस तरह ब्रिक्स सम्मेलन ने वर्ल्ड ऑर्डर को यह संदेश दिया कि वह परस्पर विरोधी हितों और तनावों के बीच भी संवाद का मंच बन सकता है।ब्रिक्स की शक्ति विविधता और सहयोग में है और सम्मेलन ने इस दिशा में खासी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकटों से मुकाबला करने के लिए लचीला रुख अख्तियार करने की बात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बिना नियमों के दुनिया एक ऐसे चौराहे जैसी है जहां ट्रैफिक लाइट ने काम करना बंद कर दिया हो। अंतरराष्ट्रीय नियमों को लिखने में सभी देशों की साझेदारी होनी चाहिए। 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन के पास होगी, लिहाजा शी जिनपिंग का यह कहना कि ब्रिक्स को इतिहास के सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म की बढ़ती भूमिका के बारे में संकेत देने वाला है।ब्रिक्स घोषणापत्र 2026 में कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं है, लेकिन उसके वर्चस्व को तगड़ी चुनौती दी गई है। खासतौर से टैरिफ वार और डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर जोर महत्वपूर्ण है। घोषणापत्र में सीमा–पार भुगतान प्रणालियों को बेहतर बनाने और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार तथा निवेश में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर चर्चा जारी रखने की बात कही गई है। ब्रिक्स के देश खासतौर पर अमेरिका के टैरिफ वार के निशाने पर रहे हैंकृचाहे चीन हो या भारत या फिर रूस। सभी के लिए इस टैरिफ के डंडे से बाहर निकलने का रास्ता खोजना प्राथमिकता रही और 11–13 सितंबर को ब्रिक्स के अलग–अलग प्लेटफॉर्म पर इस पर खूब चर्चा हुई। भारत ने संतुलित रुख अख्तियार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से गर्मजोशी भरी मुलाकातें और साथ में पौधा लगाना अलग ढंग का राजनीतिक संदेश दे रहे थे। संदेश साफ हैकृग्लोबल साउथ अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और यह दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने की दिशा में कदम है। घोषणापत्र के निशाने पर इजरायल भी है और खुलकर गाजा में हो रही हिंसा–बर्बरता के खिलाफ बोला गया हैकृ जो अपने आप में ऐतिहासिक है। घोषणापत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स के देश तमाम पक्षों से यह आग्रह करते हैं कि वे गाजा में युद्धविराम का सम्मान करें। ब्रिक्स फिलिस्तीनियों को जबरन बाहर ढकेलने के खिलाफ है और दो राष्ट्रों के निर्माण की अवधारणा के समर्थन में है। इस तरह से ब्रिक्स के तमाम देशों का फिलिस्तीन के पक्ष में आना और इजरायल के खिलाफ बोलना एक मायने में अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ बोलना है। ब्रिक्स देशों ने सम्मेलन में आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों के साथ युद्ध, टैरिफ वार और प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों पर बेहतर समझदारी विकसित की।

यूपीआई शुल्कः सुविधाओं का विस्तार या उपभोक्ता पर बोझ

ललित

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में यूपीआई केवल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि वह रोजमर्रा के आर्थिक व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर बड़े कारोबारी तक, टैक्सी से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक और घरेलू लेन–देन से लेकर व्यावसायिक भुगतान तक–यूपीआई ने पैसे के लेन–देन की आदत, गति और भाषा तीनों बदल दी हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़े शुल्क की व्यवस्था केवल बैंकिंग या फिनटेक कंपनियों का कारोबारी विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उपभोक्ता की आदत, छोटे व्यापार की लागत और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा से है। यहां एक तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। सितंबर 2026 में सरकार ने जो नया ढांचा स्पष्ट किया है, उसके अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति यानी पी2पी को यूपीआई भुगतान किसी भी राशि पर निःशुल्क रहेगा। रू.2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर भी एमडीआर नहीं है। रू.2,000 से अधिक के कुछ पी2एम यानी ग्राहक से व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर का प्रावधान किया गया है और रू.75,000 या उससे अधिक के लेन–देन पर प्रति लेन–देन अधिकतम रू. 300 की सीमा रखी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूल किया जाने वाला लेन–देन शुल्क नहीं है, बल्कि व्यापारी–पक्ष का एमडीआर है। फिर भी इस बदलाव को केवल 'शुल्क लगा या नहीं लगा' के प्रश्न तक सीमित करना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और उसकी लागत किसके हिस्से में जाए। यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सरलता और लगभग बिना लागत की अनुभूति रही है। अगस्त 2026 में यूपीआई पर करीब 24.51 अरब लेन–देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग रू.29.82 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई अब किसी वैकल्पिक भुगतान माध्यम की श्रेणी में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक जीवन के बुनियादी ढांचे में शामिल हो चुका है। यूपीआई के इस विस्तार के पीछे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। लोगों ने डिजिटल भुगतान को केवल सुविधा नहीं, स्वाभाविक व्यवहार मान लिया है। पहले दस रुपये, पचास रुपये या सौ रुपये के लिए जेब से नकद निकालना सामान्य थाय आज वही भुगतान मोबाइल से कुछ सेकंड में हो जाता है। जब कोई सेवा वर्षों तक निःशुल्क उपलब्ध रहती है तो उपभोक्ता उसके पीछे मौजूद तकनीकी, बैंकिंग और साइबर–सुरक्षा लागत को लगभग भूल जाता है। इसलिए बाद में किसी प्रकार का शुल्क या लागत सामने आने पर स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा होती है। यहीं आधुनिक बाजार व्यवस्था की एक बड़ी विसंगति दिखाई देती है। अनेक डिजिटल और उपभोक्ता सेवाएं पहले मुफ्त, अत्यंत सस्ती या भारी छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ता को उस सुविधा का अभ्यस्त बनाया जाता है, बाजार में उसका व्यवहार बदलता है और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के बाद लागत की नई संरचना सामने आती है। ओला–उबर जैसी सेवाओं से लेकर ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सदस्यता और विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं तक इस मॉडल के अलग–अलग रूप दिखाई देते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर मामले में यही रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है–यदि किसी सेवा की दीर्घकालिक लागत है तो उसकी जानकारी शुरुआत से स्पष्ट क्यों न हो? यूपीआई के मामले में यह प्रश्न और गंभीर है क्योंकि इसके उपयोगकर्ता केवल शहरी मध्यमवर्ग नहीं हैं। छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू उद्यमी, ग्रामीण उपभोक्ता और पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग भी इसके बड़े हिस्से हैं। सरकार की 2025 की प्रोत्साहन योजना में भी छोटे व्यापारियों के रू.2,000 तक के भीम–यूपीआई भुगतान को शून्य एमडीआर के दायरे में रखते हुए रू. 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और भुगतान ढांचे को मजबूत करना था। इसलिए शुल्क की किसी भी व्यवस्था का पहला सिद्धांत होना चाहिए–छोटे भुगतान और छोटे कारोबार की रक्षा। रू.100, रू.500 या रू.1,000 के भुगतान पर लागत बढ़ाने वाला मॉडल डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत जा सकता है। इसके विपरीत बड़े व्यावसायिक भुगतान से जुड़ी लागत को अलग तरीके से देखा जा सकता है, बशर्ते शुल्क पारदर्शी, सीमित और पूर्व घोषित हो तथा उसका भार अनुचित रूप से ग्राहक पर न डाला जाए। यहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। यूपीआई के व्यापक प्रसार ने कार्ड भुगतान को रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में पीछे धकेला है। यदि यूपीआई के कुछ बड़े व्यापारी लेन–देन पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारी वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर देख सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यम फिर कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे भुगतान बाजार में विविधता बढ़ सकती है, लेकिन यदि उपभोक्ता को हर माध्यम में अलग–अलग

शुल्क, सुविधा और शर्तों का सामना करना पड़े तो डिजिटल भुगतान की सरलता कमजोर भी हो सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य केवल माध्यम बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ता को बेहतर विकल्प देना होना चाहिए। दूसरी ओर यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने की भी कीमत है। भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे चलाने के लिए बैंकिंग सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियां, ग्राहक सहायता और तकनीकी उन्नयन पर लगातार खर्च होता है। जैसे–जैसे लेन–देन बढ़ते हैं, वैसे–वैसे विश्वसनीयता और क्षमता पर निवेश की आवश्यकता भी बढ़ती है। सरकार की 2025 की योजना में भी तकनीकी विफलताओं को घटाने और सिस्टम अपटाइम सुधारने को प्रोत्साहन से जोड़ा गया था। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यूपीआई की हर सेवा हमेशा मुफ्त रहे या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि उसकी लागत का न्यायपूर्ण और पारदर्शी वितरण कैसे हो। सरकार, बैंक, फिनटेक कंपनियां और भुगतान नेटवर्क यदि इस व्यवस्था से आर्थिक लाभ लेते हैं तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा, विश्वसनीयता और नवाचार पर पर्याप्त निवेश हो। शुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि बेहतर डिजिटल भुगतान व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा होना चाहिए।

एआई से खतरों के बीच मुनाफे और ताकत के दांव

राजेश

टेक्नालॉजी से मानव की तरक्की से कोई इन्कार नहीं करता है। लेकिन उसके दुरुपयोग की आशंकाओं को खारिज भी नहीं कर सकते हैं। एआई को किनारे रख दें और सोशल मीडिया के प्रभाव को देख लें तो स्थिति समझी जा सकती है। सोशल मीडिया की लत युवाओं, किशोरों के साथ सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन, उस पर कारगर रोक किसी कंपनी ने नहीं लगाई है। इन दिनों दुनियाभर खासकर अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली तबाही पर गर्म बहस छिड़ गई है। विश्व के भविष्य को लंबे समय तक प्रभावित करने वाली तकनीक में दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के साथ दिग्गज टेक्नालॉजी कंपनियों के बड़े दांव लगे हैं। एआई से मानवता के अस्तित्व को खतरों की चेतावनियों के बावजूद कोई पक्ष पीछे नहीं हटना चाहता है। अमेरिका, चीन को अपना प्रभाव कम होने और पिछड़ने की आशंका है तो टेक कंपनियों की नजर अरबों रुपए के निवेश और मुनाफे पर है। इस रस्साकशी ने उम्मीद जगाई है कि देर–सबेर एआई पर काबू पा लिया जाएगा।एआई या कृत्रिम बुद्धि के विध्वंसक नतीजों के बारे में एआई के गॉडफॉदर माने जाने वाले वैज्ञानिक ही आगाह कर रहे हैं। यहां कुछ नामी साइंटिस्ट का जिक्र काफी होगा। मांट्रियल यूनिवर्सिटी, कनाडा में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जोशुआ बेंजिओ 2023 से एआई के कारण मानव अस्तित्व को खतरे और उस पर मानवीय नियंत्रण खत्म होने के बारे में कह रहे हैं। बेंजिओ ने एआई के खिलाफ अभियान छेड़ने और सुरक्षा का सिस्टम बनाने के लिए लॉ जीरो संगठन बनाया है। लॉ जीरो बेकाबू एआई एजेंट को बेअसर करने के सेफ्टी सिस्टम बना रहा है। संगठन को जर्मनी और कनाडा की सरकारों के साथ माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया से मदद मिली है।बेंजिओ के साथ 2018 में एलन ट्यूरिंग पुरस्कार हासिल करने वाले ज्याफ्रे हिंटन ने 2023 में गूगल से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि वे एआई के जोखिमों पर अधिक स्वतंत्रता से बोलने के लिए काम छोड़ रहे हैं। हिंटन कहते हैं कि एआई मानवों से अधिक स्मार्ट हो जाएगी और सत्ता पर कब्जा करने जैसे लक्ष्य बना लेगी। उसे बंद करना या नियंत्रण में रखना असंभव हो जाएगा। गूगल के पूर्व शोधकर्ता का कहना है कि एआई का बुरे लोग दुरुपयोग करेंगे,ऑटो साइबर हमले होंगे और जैविक वायरस तैयार किए जाएंगे हैं। वे इस टेक्नालॉजी के कारण बेरोजगारी बढ़ने और चुनावों में धांधली का अंदेशा भी जताते हैं।बेंजिओ, हिंटन के साथ एआई लैब्स में काम करने वाले कई शोधकर्ता लगातार चिंता जता रहे हैं। वे कहते हैं कि एआई इस दशक के अंत तक मानवों का अस्तित्व खत्म कर देगी। इनकी चेतावनियों ने वैसा असर नहीं किया है जैसा कि 8 सितंबर को एआई लैब एंथ्रोपिक से जेकब कॉक्सन के इस्तीफे का हुआ है। कॉक्सन ने तीन साल तक ओपनएआई और एंथ्रोपिक में एआई के शक्तिशाली मॉडलों को प्रशिक्षित किया है। उनके इस्तीफे की पोस्ट को इंटरनेट पर 24 घंटे से कम समय से नौ करोड़ से अधिक व्यू मिले थे। उन्होंने सबसे बड़ा खतरा बताया यह है कि यदि हमने एआई की वर्तमान गति को धीमा नहीं किया तो निकट भविष्य में हम सब मर जाएंगे। वे कहते हैं, एआई कंपनियों में काम कर रहे सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। कॉक्सन की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। 12 सितंबर को एंथ्रोपिक के प्रमुख डैरियो अमोडेई ने एक लेख में सुझाव दिया है कि एआई पर सामूहिक रोक और संयम की जरूरत है। प्रमुख एआई लैब्स को एआई की क्षमता बेहतर बनाने की गति धीमी करना चाहिए। ओपनएआई के सैम आल्टमैन, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्सएआई के मालिक एलन मस्क का भी कहना है कि एआई मॉडलों की रफ्तार धीमी होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला कहते हैं, एआई के बड़े मॉडलों को समाज की मदद और मानवीय नियंत्रण के सिद्धांतों से निर्देशित होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे कीमती टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग कहते हैं, एआई को नियंत्रित करने के लिए किसी नए कानून या नियमों की जरूरत नहीं है। उनका कहना है, नियंत्रण का काम बाजार की ताकतें करेंगी। हुआंग जोर देते हैं, तेजी से आगे बढ़ें लेकिन अगर किसी बिंदु पर लगता है कि कंपनी या उसके प्रोडक्ट काबू से बाहर जा रहे हैं तो ठहर जाइए और सुधार कीजिए। कुछ टेक्नालॉजी कंपनियां एआई की गति को धीमी करने की बात तो करती हैं लेकिन वे निर्णायक कदम नहीं उठा रही हैं। दरअसल, उनका मुनाफा और बाजार मूल्य एआई पर बहुत हद तक निर्भर है। अलग–अलग कंपनियों ने सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और एआई मॉडलों के दम पर अरबों रुपए कमाए हैं। इनका बाजार मूल्य कई देशों के जीडीपी से आगे है। इस समय एनवीडिया का बाजार मूल्य 5.35 लाख करोड़ रुपए, एपल 450 लाख करोड़ रुपए, गूगल 393 लाख करोड़ रुपए, माइक्रोसॉफ्ट 355 लाख करोड़ रुपए, अमेजन 266 लाख करोड़ रुपए और मेटा का मूल्य 158 लाख करोड़ रुपए है। बड़ी टेक कंपनियां एआई पर काफी पैसा लगा रही हैं। अमेजन, गूगल, फेसबुक की मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने 2024–25 और 2025–26 में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी खर्च के बतौर 95 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। ओपनएआई और एंथ्रोपिक में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और जापान के सॉफ्ट बैंक ने निवेश किया है। लिहाजा,उनके लिए यह काम समेटना या धीमा करना मुश्किल नहीं है लेकिन कारोबार की होड़ उनके कदम रोकती है। निवेशक भी खुले हाथ से पैसा लगा रहे हैं। 2020 में निवेशकों ने रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग में 2.1 लाख करोड़ रुपए लगाए थे। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये सभी तकनीक एआई से जुड़ी हैं। एआई की होड़ देशों और कंपनियों के बीच टेक्नालॉजी के कारण बढ़ती असमानता पर भी रोशनी डालती है। एआई में भारत सहित कई देशों की कंपनियां निवेश कर रही हैं। लेकिन, वे इनोवेशन में पीछे हैं। केवल फ्रांस की मिस्ट्रल अमेरिकी, चीनी कंपनियों का थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकती है। इसी तरह एआई में बड़ी कंपनियों को ज्यादा कामयाबी मिली है। ओपनएआई और एंथ्रोपिक का आकार छोटा है पर वे इनोवेशन में अव्वल हैं। चीन की अलीबाबा, डीपसीक और जेडएआई जैसी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले कम खर्च में एआई मॉडल बना रही हैं। एआई से साइंस, टेक्नालॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती जैसे क्षेत्रों में असीमित संभावनाओं के साथ देशों की सामरिक ताकत भी जुड़ी है।

भारत में नीरो और किम जोंग उन का जिक्र

गोपाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को 76 बरस के हो गए। उन्हीं की बनाई परिपाटी के मुताबिक उन्हें सत्ता से हटकर भाजपा के मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन कर रह जाना चाहिए था। लेकिन नरेन्द्र मोदी अपने लिए अलग नियम बनाते हैं और दूसरों के लिए अलग। जैसे प.एशिया के तनाव के कारण जो वैश्विक आर्थिक संकट आया, उसमें मोदी ने जनता से अपील की कि वे विदेश न जाएं, लेकिन उसके फौरन बाद खुद एक के बाद एक विदेश यात्राओं पर निकल गए। मोदी ने जनता से ये अपील भी की थी कि तेल का इस्तेमाल कम करें, इस के बाद भाजपा नेताओं ने कुछ दिनों तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने और सार्वजनिक यातायात साधनों से सफर की नौटंकी भरे वीडियो बनवाए, लेकिन अब मोदी के जन्मदिन पर भाजपा और भाजपा सरकारें लाखों–करोड़ों दीए जलवा रही है। इससे भी जाहिर होता है कि मोदी की कथनी और करनी एक नहीं है।भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कुछ दिन पहले ही अपील की थी कि 17 सितंबर की शाम को सभी अपने–अपने घरों में दीए जलाएं, इसे उन्होंने आशीर्वाद का दीया करार दिया। पता नहीं नरेन्द्र मोदी की सत्ता को लेकर भाजपा कितना असुरक्षित महसूस करती है, जो तीन बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके लिए भाजपा नेताओं को अपील करनी पड़ती है। चुनाव के वक्त ऐसे प्रचार करना, वोट मांगना, सत्ता के लिए आशीर्वाद मांगना फिर भी जायज लगता है, लेकिन जब देश में चारों तरफ जनता दुखों और तकलीफों में घिरी दिखाई दे, तब खुद को 140 करोड़ लोगों के परिवार का मुखिया कहने वाला व्यक्ति अपने जन्मदिन का जश्न जबरदस्ती मनवाए तो इससे बड़ी विडंबना किसी लोकतांत्रिक देश के लिए नहीं हो सकती।नरेन्द्र मोदी चाहते तो भाजपा अध्यक्ष की अपील पर विनम्रता से इंकार करते हुए कह सकते थे कि जब मेरे देशवासी तकलीफों में हैं, तो मैं अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाना चाहता। इससे उनका कद वाकई बड़ा होता। लेकिन इसकी जगह नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस तरह के आशीर्वाद मिलने पर खुशी ही जताई है। जाहिर है उन्हें रत्ती भर भी जनता की परवाह नहीं है। 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, तो सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर को अपना जन्मदिन न मनाने की अपील की थी, इसी तरह 2019 में उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया था। इसी तरह 2022 में जब अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो 9 जून को जन्मदिन से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि, श्मैं देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरह का जश्न न मनाएं।श इससे पहले 2020 और 2021 में कोविड महामारी के दौरान भी राहुल ने ऐसी ही अपील की थी।लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक जीवन में नेताओं का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नरेन्द्र मोदी में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति रत्ती भर भी नजर नहीं आती। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, जैसी मिसालें भी इस व्यवहार के आगे हल्की नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन की भाजपा और सरकारी पहलों पर एक टिप्पणी पढ़ने मिली बधाई हो किम जोंग उन हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम इस तरह भारतीय संदर्भ में आना लोकतंत्र के लिए उभर चुके खतरनाक लक्षणों को दिखा रहा है। गनीमत है कि भारत में हम अब भी कम से कम यह लिख–बोल पा रहे हैं कि सरकार का कौन सा फैसला सही है, कौन सा गलत। विपक्ष की आवाज को अमीर मीडिया घरानों में भले जगह न दी जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्ष को सुना जा रहा है। उ. कोरिया में यह सब मुमकिन नहीं है। पर भारत में भी कब तक मुमकिन रह पाएगा, इसकी चिंता बढ़ती जा रही है।इस समय बाढ़ की भारी तबाही से बिहार जूझ रहा है, कम से कम 50 लाख लोग बाढ़ के खतरों का सामना कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही असम में ऐसी ही तबाही आई थी। इधर दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे की भयावहता अब तक कायम है। मणिपुर में तो पिछले तीन सालों से अशांति बनी हुई है। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके अपने घर जातीय हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन राहत शिविरों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। 8 जिलों में कम से कम 640 मौतें दर्ज की गई हैं। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है। मध्यप्रदेश में बालाघाट में कम से कम 30 बैगा आदिवासी बच्चों की मौत दूषित पानी के कारण हो चुकी है। ये सारे हालिया मामले हैं, इनके अलावा नीट पेपर लीक के कारण 24 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान ले ली है, किसानों की आत्महत्या

के मामले भी थम नहीं रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार से परिवारों की खुशियां चली गई हैं। ऐसे निराशाजनक माहौल में नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन किसी राष्ट्रीय पर्व की तरह भाजपा मना रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद निकट भविष्य में 2 अक्टूबर की जगह 17 सितम्बर को राष्ट्रीय पर्व में शामिल कर लिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। दैनिक समाचार–पत्र पढ़ें भाजपा जानती है कि जब तक सत्ता उसके हाथ में है, जब तक संवैधानिक संस्थाएं उसके सामने घुटनों पर बैठी रहेंगी, वह पूरी उच्छृंखलता दिखा सकती है। इस समय यही होते हम देख रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि तमाम भाजपा शासित राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से नरेन्द्र मोदी जन्मदिवस के कार्यक्रमों का सरकारीकरण कर रहे हैं। तमाम राज्यों में स्कूल शिक्षकों से कहा गया है कि वे स्कूल के बच्चों के वीडियो बनाकर पोस्ट करें, जिनमें मोदी की तारीफ होना चाहिए। शिक्षा अधिकारी निगरानी कर रहे हैं कि स्कूलों में दीए जलाए जाएं। आंगनबाड़ियों, स्कूलों, सरकारी अस्पतालों सब जगह दीए जलाने के निर्देश दिए गए। लाखों–करोड़ों दीए जलाने के लिए धन की व्यवस्था कहां से हुई, क्या सरकारों ने किसी निविदा प्रक्रिया के जरिए तय किया कि कौन सी एजेंसी कहां से तेल, दीयों, बातियों समेत बाकी सामग्री खरीदेगी।

बंथरा और कृष्णानगर के दो दबंग छह माह के लिए जिला बदर

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था की अदालत ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम–1970 के तहत बंथरा और कृष्णानगर थाना क्षेत्र के दो आरोपियों को गुंडा घोषित करते हुए छह–छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित कर दिया है।न्यायालय में अधिनियम की ध ारा–3 के तहत हुई कार्रवाई के बाद बंथरा थाना क्षेत्र के कस्बा बंथरा में हनुमान मंदिर के निकट रहने वाले करीब 33 वर्षीय आदित्य द्विवेदी पुत्र कृष्ण कुमार द्विवेदी को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसी तरह कृष्णानगर थाना क्षेत्र के पूरन नगर सरदारीखेड़ा निवासी करीब 32 वर्षीय सूरज कुमार वर्मा पुत्र रामनाथ लोधी उर्फ रामनाथ वर्मा को भी छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ लोक शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। जिला बदर की अवधि के दौरान दोनों को लखनऊ की सीमा से बाहर रहना होगा। पुलिस द्वारा आदेश के अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

जनेश्वर मिश्र पार्क में कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास एक युवती के ऊपर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता अनामिका सिंह की तहरीर पर पुलिस ने शहनवाज और दानिश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार विनीत खंड, गोमतीनगर निवासी अनामिका सिंह ने तहरीर में बताया कि 16 सितंबर की सुबह करीब 6रू30 बजे वह जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार पर चाय पीने गई थीं। इसी दौरान उनका मित्र शहनवाज अली अपने साथी दानिश के साथ कार संख्या यूपी32केएच8090 से वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने युवती से विवाद करते हुए उसके साथ गाली–गलौज की।पीड़िता का आरोप है कि शहनवाज ने जान से मारने की नीयत से उसकी ओर कार बढ़ा दी। बचने के प्रयास में वह उछलकर कार के बोनट पर चढ़ गई और वाइपर पकड़ लिया। इसके बावजूद कार चालक ने उसे गिराने के बाद उसके ऊपर कार का पहिया चढ़ाने का प्रयास किया। पीड़िता के अनुसार वह टक्कर लगने से बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद उसकी छोटी बहन, बुआ और अन्य लोगों ने उसे उठाया और तत्काल डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया।तहरीर में आरोप लगाया गया है कि दानिश ने भी युवती के साथ गाली–गलौज की और शहनवाज से कार चढ़ाकर वहां से भागने के लिए कहा। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार को सौंपी है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

खरीफ 2026 में 23.58 लाख किसानों का फसल बीमा, 3.04 लाख क्षति दावों पर सर्वेक्षण जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 मौसम में अब तक 23.58 लाख किसानों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जा चुका है। प्रदेश में कुल 1.10 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड खातों में से 69.12 लाख खाते अपात्र श्रेणी के हैं, जबकि 20. 11 लाख खाते अभी संतृप्त होने से शेष हैं। सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को योजना से आच्छादित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी थी।योजना की अद्यतन प्रगति के अनुसार खरीफ 2026 मौसम में पिछले खरीफ 2025 की तुलना में 2.94 लाख अधिक किसानों ने फसल बीमा कराया है, जो 14.25 प्रतिशत की वृद्धि है। खरीफ 2025 में 20.63 लाख किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया था, जिसके सापेक्ष 7.31 लाख किसानों को 812.76 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार रबी 2025–26 में 18.69 लाख बीमित किसानों के सापेक्ष अब तक 1.69 लाख किसानों को 135.30 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2017–18 से 2025–26 तक की अवधि में प्रदेश के 69. 32 लाख किसानों को कुल 6,125.54 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है।वित्तीय वर्ष 2026–27 में किसान क्रेडिट कार्ड खातों के नवीनीकरण और नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का 83.90 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से सतत विकास लक्ष्यों को गति देने पर मंथन

लखनऊ, (संवाददाता)। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रयासों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बुध ावार को होटल क्लार्क्स अवध में 'सशक्त भविष्य रू शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को गति' विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल विकास और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, नियोजन आलोक कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। सफल प्रयासों और नवाचारों को साझा कर प्रभावी रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं। आंकड़ों, प्रौद्योगिकी और नवाचार का बेहतर उपयोग कर योजनाओं के परिणामों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।पहले सत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों की चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बेहतर परिणामों के लिए आंकड़ों, तकनीक और नवाचार के प्रभावी उपयोग को जरूरी बताया।

स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पोषण व्यवस्था मजबूत करने के साथ बढ़ा रहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा–निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ प्रदेश की पोषण व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा टेक होम राशन संयंत्रों में पोषाहार का उत्पादन कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों तक पोषाहार पहुंचाया जा रहा है।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आजीविका के नए अवसर प्राप्त कर अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। टेक होम राशन इकाइयों के माध्यम से एक ओर जहां ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय का स्थायी अवसर मिल रहा है, ।

टाइल्स गोदाम में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने साढ़े तीन घंटे जाम किया मार्ग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चौकियां रोड स्थित बालाजी टाइल्स के गोदाम में काम करने वाले एक युवक की शुक्रवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को जौनपुर–शाहगंज मार्ग पर रखकर करीब साढ़े तीन घंटे तक चक्का जाम किया। इससे मार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। मृतक की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र के परमानतपुर मोहल्ला निवासी भोलू (30) पुत्र मुन्ना के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार भोलू बालाजी टाइल्स के गोदाम में काम करता था। शुक्रवार दोपहर वह किसी काम से गोदाम के अंदर गया था। कुछ देर बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला और घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने युवक की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना की सूचना मिलते ही नगर क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता, शहर कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह समेत आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सड़क जाम की सूचना पर समाजवादी पार्टी की मछलीशहर विधायक डॉ. रागिनी सोनकर भी मौके पर पहुंचीं और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने सरकारी नियमों के तहत आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया। सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अध िकारियों के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम समाप्त कर दिया। इसके बाद यातायात सामान्य कराया गया।

सेवा संकल्प अभियान के अन्तर्गत मेडिकल कालेज जौनपुर एवं रोटरी क्लब जौनपुर के संयुक्त तत्वावधान में मेडिकल कालेज कैंपस में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर एवं रोटरी क्लब जौनपुर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा संकल्प अभियान माह के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर को हरित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ–साथ समाज में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता का संदेश देना रहा। कार्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो0 (डा0) आर0बी0 कमल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो0 (डा0) ए0ए0 जाफरी, चीफ प्रॉक्टर प्रो0 रुचिरा सेठी, डीन एकेडमिक प्रोफेसर तबस्सुम यासमीन, कैंपस प्रभारी डा0 संजीव यादव, डा0 विनोद कुमार, डा0 जितेंद्र कुमार, डा0 आशुतोष सिंह, डा प्रियंका सिंह, डा0 अर्चना चौधरी, डा श्वेता सिंह, दीपिका शाव, डा0 मिथिलेश सिंह, डा0. अबू समा खान डॉ0 जयंत शर्मा एवं डा0 संदीप सिंह सहित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों द्वारा पौधरोपण किया गया। इसी क्रम में रोटरी क्लब जौनपुर की ओर से अध्यक्ष शिवांशु श्रीवास्तव, सचिव संदीप सेठ, प्रेसिडेंट इलेक्ट डा0 बृजेश कन्नौजिया, जोनल सेक्रेटरी श्याम वर्मा, पर्यावरण निदेशक ज्योति सिंह, रविकांत जायसवाल, डा0 सुधांशु टंडन, संजय जायसवाल, शाहिद शम्स अब्बास, कृष्ण कुमार मिश्र एवं दुर्गेश तिवारी द्वारा भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रो0 (डा0) आर0बी0 कमल ने कहा कि यह कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान माह के अन्तर्गत आयोजित किया गया जिसका मूल उद्देश्य वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ–साथ स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में अध िक से अधिक पौधों का रोपण एवं उनका संरक्षण संस्थान को हरित परिसर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध यक्ष डा0 अनुज सिंह सहयोगी चिकित्सक डा0 मुदित चौहान, डा0 पूजा पाठक, डा0 नवीन कुमार, डा0 अनिल कुमार एवं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अन्य चिकित्सक व कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया। चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन एवं रोटरी क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाने तथा भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन ने रोटरी क्लब जौनपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया।

फूस के घर में सो रही वृद्धा को मार डाला, शव को चारपाई से नाले के पास खींच ले गया

लखनऊ, (संवाददाता)। बहराइच के कतर्नियाघाट वन क्षेत्र में तेंदुए का खौफ अब जानलेवा हो गया है। बृहस्पतिवार देर रात बाजपुर बनकटी ग्राम पंचायत के सीतारामपुरवा नहर के किनारे तेंदुए ने फूस के कच्चे घर में सो रही 86 वर्षीय वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया और शव को घर के पीछे नाले में खींच ले गया। मृतका की पहचान फूलवती पत्नी स्व. प्रभु निवासी सीतारामपुरवा, नहर बाजार, बाजपुर बनकटी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार वृद्धा रात में अपने फूस के कच्चे घर में अकेली सो रही थीं। घर का दरवाजा

नहीं था, सिर्फ टाट पड़ा था। इसी दौरान तेंदुआ घर में घुस गया और वृद्धा पर हमला कर दिया। चीख सुनकर जब तक परिजन और पड़ोसी पहुंचे, तेंदुआ वृद्धा को घसीटकर घर के पीछे नाले में ले जा चुका था। सुबह ग्रामीणों ने नाले में वृद्धा का शव देखा तो गांव में चीख–पुकार मच गई। सूचना पर कतर्नियाघाट रेंज की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक वृद्ध महिला की पांच बेटियां सुनीता, महारानियाँ, रमावती, महारानी जिनकी शादी हो चुकी है, इसके अलावा एक बेटा है सोहन जिसकी शादी नही हुई है वह माँ के साथ रहता कि लेकिन अभी वह बाहर मजदूरी करने गया है। एक हफ्ते में तीसरी घटनारू ग्रामीणों का कहना है कि सीतारामपुरवा, चफरिया और नहर बाजार इलाके में पिछले एक हफ्ते से तेंदुए की लगातार चहलकदमी देखी जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाने, गश्त बढ़ाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। घटना रेंज सुजौली की है। रेन्जर नीरज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया और कहा हर संभव मदद दिया जाएगा शव को पोस्टमार्टम के लिए सुजौली थाना प्रभारी गोविंद वर्मा ने भेज दिया है। कल इसी जगह तेंदुए ने एक बकरी को निवाला बनाया था लेकिन मौके पर कोई भी वन कर्मी नही पहुचा था, अगर समय से वन विभाग एक्टिव हो जाता तो सायद महिला की जान न जाती।

डॉक्टर ने मरीज को निजी अस्पताल भेजने से किया इन्कार

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओपीडी से मरीज को निजी अस्पताल भेजने के मामले में आरोपी डॉक्टर ने बयान दर्ज करा दिया है। बयान में उसने आरोपों से इन्कार किया है। विभागाध्यक्ष ने मामले की रिपोर्ट कुलपति को सौंपी है। बस्ती के कुदरहा ब्लॉक निवासी पुष्पा (54) किडनी रोग से पीड़ित थीं। परिजन उन्हें केजीएमयू नेफ्रोलॉजी विभाग ले गए थे। आरोप है कि बॉन्ड के तहत तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ने फेफड़े में संक्रमण बताया और केजीएमयू में प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए मरीज को दुबग्गा स्थित फाह हॉस्पिटल भेजा दिया। वहां आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी परिजनों से करीब एक लाख रुपये वसूले गए। बाद में मरीज की मौत हो गई। पुष्पा के बेटे विजय कुमार चौधरी ने डॉक्टर पर इलाज के नाम पर वसूली का आरोप लगाया था। नेफ्रोलॉजी के विभागाध यक्ष को मामले की जांच सौंपी गई थी। आरोपी डॉक्टर लगातार निजी अस्पताल में मरीज का इलाज न करने का दावा करता रहा। लीक हुई ऑडियो में विभागाध्यक्ष का नाम लेने पर डॉक्टर ने लिखित माफी मांगी है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह के अनुसार, परिजनों का बयान व शिकायती पत्र अभी नहीं मिला है। वायरल रिकॉर्डिंग के साथ अन्य साक्ष्य जांच में शामिल किए गए हैं।

2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन से व्यापारियों में चिंता, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में व्यापारियों ने 2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी–आधारित यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है। शनिवार को जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को सौंपा। जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने कहा कि देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे आम नागरिकों, व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए लेनदेन आसान और तेज हुआ है। व्यापारी वर्ग भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने में लगातार सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से 2,000 से अधिक के कुछ व्यापारी–आधारित यूपीआई लेनदेन पर लागू होने की व्यवस्था से छोटे और मध्यम व्यापारियों में चिंता बढ़ी है। किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, हार्डवेयर, दवा, ऑटो पार्ट्स और अन्य छोटे प्रतिष्ठानों में कई बार एक ग्राहक का भुगतान 2,000 से अधिक हो जाता है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। व्यापारियों का कहना है कि छोटे कारोबार में लाभ मार्जिन सीमित होता है। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क का असर सीधे उनकी आय पर पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि लंबे समय तक बढ़ी हुई लागत व्यापारी स्वयं वहन नहीं कर पाएंगे और इसका असर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है। व्यापार मंडल ने सरकार से व्यवस्था पर पुनर्विचार करने, छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाली मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की।

बटला हाउस मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बटला हाउस मुठभेड़ की 18वीं बरसी पर शनिवार को राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुठभेड़ की न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को सौंपा। प्रदर्शन जिलाध्यक्ष शाहिद अली खान के नेतृत्व में किया गया। जिलाध्यक्ष शाहिद अली खान ने कहा कि 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में हुई मुठभेड़ में दो मुस्लिम युवकों आतिफ और साजिद तथा एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई मुस्लिम युवकों को फंसाया गया, जिससे उनका जीवन प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल ने मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आजमगढ़ से दिल्ली तक आंदोलन किया था। संगठन आज भी इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। पार्टी नेता हस्सान अहमद काशमी ने कहा कि बटला हाउस मुठभेड़ के बाद तत्कालीन सरकार ने अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 176 के तहत पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामलों में मजिस्ट्रेट जांच का प्रावध ान था, लेकिन इस मामले में जांच नहीं कराई गई। राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल के नेताओं ने कहा कि मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी और दो युवकों की मौत की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने सरकार से मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की और कहा कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

पिछड़े और अतिपिछड़े समाज में असुरक्षा का माहौल, सरकार की कानून–व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

लखनऊ, (संवाददाता)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े, अतिपिछड़े और वंचित समाज के बीच असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। प्रदेश सरकार शून्य सहनशीलता की नीति और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है।उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि गोंडा में निषाद समुदाय के एक व्यक्ति की सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखने के बाद दबंगों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप है। मथुरा में निषाद समुदाय के एक व्यक्ति के साथ गंभीर मारपीट किए जाने के बाद उसके अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आई है। अयोध्या में मौर्य समाज के एक युवक की हत्या का मामला भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से पिछड़े वर्ग में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और अपराध तथा हत्याओं की घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती जा रही हैं।उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन मनोज यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और पिछड़े तथा अतिपिछड़े वर्ग के लोगों पर ज्यादती बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोंडा में निषाद समाज के युवक की हत्या और मथुरा में निषाद समाज के लोगों के साथ मारपीट के मामले गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने के बाद वहां भी हमला किए जाने का आरोप है और निषाद समुदाय का एक युवक अभी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है।मनोज यादव ने अयोध्या में मौर्य समाज के युवक की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि उसे कथित तौर पर एक निश्चित तारीख को हत्या किए जाने की धमकी दी गई थी, लेकिन उससे दो दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में संगठित तरीके से हत्याएं हो रही हैं। उनका कहना था कि यदि किसी घटना में दलित या पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो बुलडोजर कार्रवाई की जाती है।

भाजपा का नकारात्मक अभियान ही उसका हथियार, समाज में नफरत फैलाना एजेंडा - अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ डिजिटल अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नकारात्मक अभियान भाजपा का हथियार है। भाजपा की भाषा अलोकतांत्रिक है और उसका एजेंडा समाज में नफरत फैलाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की विरोधी है। सरकार की नीतियों के चलते मुनाफाखोरी बढ़ी है और महंगाई से आम उपभोक्ता परेशान है। भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कथित कुशासन से त्रस्त है।अखिलेश यादव बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। भाजपा के अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं और जनता उसके खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 2027 में पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित हो, सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर उसका समर्थन करें और उसे जिताकर विध ायक बनाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक

विचारों के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और जनता पार्टी के साथ है।अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कानून–व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है तथा अपराधी बेखौफ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर दिन हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कानून–व्यवस्था तथा अपराध पर शून्य सहनशीलता का सरकार का दावा सही नहीं है।उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराध रोकने के बजाय भाजपा के राजनीतिक विरोधियों को परेशान और प्रताड़ित करने में लगी है।

टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां बनीं ककरहवा देवकाली की पहचान

अयोध्या।साकेत नगर वार्ड स्थित मोहल्ला ककरहवा देवकाली इन दिनों बदहाल सफाई व्यवस्था और जर्जर सड़कों की समस्या से जूझ रहा है।यहाँ जगह–जगह लगे कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं।एक ओर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टाइफाइड,डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को साफ–सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है,वहीं दूसरी ओर ककरहवा देवकली में गंदगी और जलभराव जैसी स्थिति इन अभियानों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है।नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से उनमें गंदगी जमा है और दुर्गंध से लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है।स्थानीय लोगो का कहना है कि इस मोहल्ले की कई सड़कें भी टूट चुकी हैं।नालियों को ढकने के लिए रखे गए पत्थर कई स्थानों से गायब हैं। जिससे खुले नाले हादसे का कारण बन सकते हैं।बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को यहां से गुजरते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ककरहवा देवकाली में स्कूल और मंदिर भी स्थित हैं।ऐसे में छात्रों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है। मोहल्ले में फैली गंदगी और नालियों से उठती दुर्गंध के बीच लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त व स्थानीय पार्षद मंसूर अली से इस समस्या की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी।स्थानीय लोगों ने मोहल्ले में नियमित सफाई, नालियों की मरम्मत, गायब पत्थरों को दोबारा लगाए जाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की है। लोगों का कहना है कि बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान तभी प्रभावी होगा, जब मोहल्लों में सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हो।

रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम, एक यूनिट रक्त से बच सकती है जान

गोरखपुर, (संवाददाता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गोरखनाथ चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और एम्स में आयोजित शिविरों में भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व आमजन ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व गोरखपुर के प्रभारी अभिजात मिश्र ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि रक्तदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवाओं व कार्यकर्ताओं को आगे आकर नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित होना चाहिए। महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। यह प्रयास समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। रक्तदान करने वालों में मनोज अग्रहरी, राजन निषाद, चंद्रशेखर सिंह, कर्मवीर सिंह, आकाश श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, अनुराग दीप, सागर चौरसिया, राहुल गुप्ता, आशुतोष उपाध्याय, तेज प्रताप कुमार, प्रशांत गुप्ता, दीपक उपाध्याय, साहिल श्रीवास्तव, श्वेता सिंह, सूरज कुमार, ओपी राय, बादल कुमार, विशाल निषाद, पराग सहित अन्य लोग शामिल रहें।

बेटी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए परिजन

गोरखपुर, (संवाददाता)। नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में बुधवार को बंद मकान का ताला तोड़कर चोर सोने–चांदी के जेवर और 40 हजार रुपये नकद उठा ले गए। परिवार के सभी सदस्य बेटी के ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए थे। वार्ड संख्या 12 निवासी रमेश चंद ने पुलिस को दी तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री प्रीति का बुधवार को कस्बे के एक निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। इसके चलते परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में मौजूद थे, और मकान में कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला काटकर घर में प्रवेश किया। इंस्पेक्टर क्राइम राजेश कुमार यादव ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है।

परिवहन विभाग ने छः दिन में 20 स्कूली वाहनों का चालान कर तीन वाहन किये सीज

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने जिले में बिना फिटनेस और बिना परमिट संचालित हो रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 'मिशन सेफ फ्यूचर 3.0' के तहत 14 से 19 सितंबर तक चलाए गए विशेष अभियान में 20 स्कूली वाहनों का चालान किया गया, जबकि तीन वाहनों को बंद कराया गया।यह अभियान उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के 7 सितंबर 2026 के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाया जा रहा है।अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन के साथ स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।जनपद में अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीमों ने स्कूल वाहनों की जांच की। जांच में बिना फिटनेस और बिना परमिट संचालित पाए गए वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।अभियान उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अयोध्या राजकुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विश्व जीत प्रताप सिंह और संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय झा के निर्देशन में चलाया जा रहा है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यात्रीध्मालकर अधिकारी और मोटर यान निरीक्षकों की टीमें वाहनों की जांच कर रही हैं।परिवहन विभाग की कार्रवाई केवल छह दिवसीय विशेष अभियान तक सीमित नहीं है।1 अप्रैल से 13 सितंबर 2026 तक अयोध्या में 160 वाहनों का चालान किया जा चुका है, जबकि 52 वाहनों को बंद कराया गया। विभाग के अनुसार स्कूली वाहनों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खासतौर पर फिटनेस, परमिट और बच्चों की सुरक्षित यात्रा से जुड़े मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर सख्ती की जा रही है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ आरपी सिंह का कहना है कि स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन कराना अभियान की प्राथमिकता है।विभागीय टीमें स्कूल वाहनों की स्थिति और वैध दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने 18 हजार रुपये मानदेय की उठाई मांग

अयोध्या।महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपये किए जाने की मांग की गई।संघ ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं महिला एवं बाल विकास तथा पोषण संबंधी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद मानदेय में की गई हालिया वृद्धि से कार्यकत्रियों में असंतोष है। शासन के पत्र संख्या 2964/68–1–2026 (1420460) के अनुसार कार्यकत्रियों के मानदेय में 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि के साथ पीएलआई के रूप में क्रमशः 2500 और 1250 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।संघ ने मांग की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को संविदा परिषद के मानकों के अनुरूप रखते हुए न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय दिया जाए।साथ ही पोषण ट्रैकर में जीपीएस की अनिवार्यता से आ रही समस्याओं का हवाला देते हुए इसे पूर्व की भांति बिना जीपीएस के संचालित किए जाने की मांग की गई।

ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष सरोज सिंह, महामंत्री निर्मला मिश्रा, मंत्री गीता यादव, सोनिका मिश्रा, मालती यादव, सरिता सोनकर, आराधना जगधारी पांडे, नीलम यादव, सुमन मौर्य, विजयलक्ष्मी, मीना, शीला, कमलेश, गिरजा यादव सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां शामिल रहीं।

साइबर ठगी के पीड़ितों को अयोध्या साइबर थाना ने लौटाए 12.04 लाख रुपये

अयोध्या। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम थाना अयोध्या की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में ठगी के शिकार आठ लोगों को 12 लाख 4 हजार 600 रुपये की धनराशि वापस कराई है।इस संबंध मे प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम अरशद ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर संबंधित बैंक एवं अन्य स्तरों पर पत्राचार और समन्वय कर यह कार्रवाई की गई। बताया कि कुछ पीड़ितों से सामान उपलब्ध कराने के नाम पर 2.30 लाख और 2.49 लाख रुपये की ठगी की गई थी।एक मामले में खाते से बिना जानकारी यूपीआई के माध्यम से 1.80 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि जमीन के क्रय–विक्रय के नाम पर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई थी। इसके अलावा फोन हैक कर अलग–अलग मामलों में भी धनराशि निकाले जाने की शिकायतें सामने आई थीं।इस सराहनीय कार्य मे उनके अलावा हेड कांस्टेबल सूर्य विजय सिंह, कांस्टेबल प्रवीण दीक्षित और कांस्टेबल हरिवीर सिंह शामिल रहे।

परिवहन विभाग ने 6 दिन मे 20 स्कूली वाहनों का चालान कर 3 वाहन किये सीज

अयोध्या।परिवहन विभाग ने जिले में बिना फिटनेस और बिना परमिट संचालित हो रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ 'मिशन सेफ फ्यूचर 3.0' के तहत 14 से 19 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया गया।अभियान में 20 स्कूली वाहनों का चालान किया गया,जबकि तीन वाहनों को सीज किया गया।एआरटीओ (परिक्षेत्र) अयोध्या राजकुमार सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विश्वजीत प्रताप सिंह और संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजय झा के निर्देशन में चलाया गया।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यात्रीध्मालकर अधिकारी और मोटर यान निरीक्षकों की टीमें वाहनों की जांच कर रही हैं।एआरटीओ प्रशासन डाक्टर आर पी सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की कार्रवाई केवल छह दिवसीय विशेष अभियान तक सीमित नहीं है। 1 अप्रैल से 13 सितंबर 2026 तक अयोध्या में 160 वाहनों का चालान किया जा चुका है, जबकि 52 वाहनों को बंद कराया गया।विभाग के अनुसार स्कूली वाहनों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सवारी बैठाने को लेकर प्राइवेट बस और टेंपो चालकों में मारपीट का वीडियो वायरल

अयोध्या।शनिवार को थाना कैंट क्षेत्र के लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सहादतगंज ओवरब्रिज के पास सवारी बैठाने को लेकर प्राइवेट बस और टेंपो चालकों के बीच जमकर मारपीट हो गई।दोनों पक्षों में सड़क पर ही लात–घूंसे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।राहगीरों ने बीच–बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया।बताया जा रहा है कि सवारी बैठाने को लेकर प्राइवेट बस और टेंपो चालकों के बीच विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना थाना कैंट क्षेत्र की बताई जा रही है।वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो में मारपीट करते दिखाई दे रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मे दिखाई दे रही प्राइवेट बस को लखनऊ से अयोध्या स्थित थाना कैंट पर लाने के लिए पुलिस गई है।वही पीड़ित पक्ष से तहरीर ली जा रही है।तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मारपीट करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अब एआई सिस्टम बता देगा हड्डियों की उम्र भी, 6 महीने तक सटीक अनुमान

गोरखपुर, (संवाददाता)। बच्चों की हड्डियां कितनी विकसित हुई हैं और उनकी उम्र के हिसाब से उनका विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए एमएमएमयूटी के छात्रों ने एक एआई सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम हाथ और कलाई के एक्स–रे को देखकर बच्चे की बोन एज (हड्डियों की उम्र) का अनुमान लगा सकता है। एमएमएमयूटी के छात्र अमर्त्य पांडेय और सक्षम शर्मा ने डॉ. रितेश मौर्य और डॉ. अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन में यह 'एआई आधारित बाल अस्थि आयु पूर्वानुमान प्रणाली' तैयार की है। यह सिस्टम कंप्यूटर विजन तकनीक के जरिए हाथ और कलाई के एक्स–रे का विश्लेषण करता है और हड्डियों की परिपक्वता के आधार पर बोन एज का अनुमान लगाता है। इससे डॉक्टरों को बच्चे की हड्डियों के विकास का आकलन जल्दी और एक समान तरीके से करने में मदद मिल सकती है। सिस्टम को तैयार करने के लिए 12,715 एक्स–रे तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। इनमें रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका (आरएसएनए) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के बोन एज से जुड़े डेटासेट शामिल हैं। सिस्टम में प्री–ट्रेंड कन्वनेक्स्ट–लार्ज (पहले से प्रशिक्षित एआई मॉडल) तकनीक का उपयोग हुआ है। मॉडल की क्षमता जांचने के लिए केवल प्रशिक्षण में इस्तेमाल किए गए एक्स–रे पर निर्भर नहीं किया गया। स्वतंत्र डेटासेट पर भी इसका परीक्षण किया गया। आईसीएमआर और आईआईटी कानपुर से जुड़े स्वतंत्र परीक्षण में सिस्टम के अनुमान और वास्तविक हड्डी की उम्र के बीच औसत अंतर करीब छह महीने रहा।इससे यह जांचने में मदद मिली कि प्रशिक्षण में इस्तेमाल नहीं किए गए नए एक्स–रे पर सिस्टम कैसा प्रदर्शन करता है। छात्रों के इस प्रोजेक्ट ने आईसीएमआर–एनएचए–आईआईटी कानपुर हैकाथॉन में भी जीत हासिल की है। बच्चों की हड्डियों की उम्र जानने के लिए अभी ग्रीलिच–पाइल और टैनर–व्हाइट हाउस विधियां प्रचलित हैं।

सराफा दुकान में घुसकर कर्मचारी को मारी गोली, सोने–चांदी के आभूषण लेकर भागे, पुलिस अलर्ट

वाराणसी, (संवाददाता)। सीमा से सटे मप्र के सिंगरौली जिले के विन्ध्यनगर थाना क्षेत्र की जयंत चौकी अंतर्गत बजरंग परिसर स्थित कंचन ज्वेलर्स में गुरुवार शाम चार हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे कर्मचारी राहुल विश्वकर्मा को गोली मारने के साथ ही उसके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। इसके बाद कर्मचारी के अचेत होने का फायदा उठाकर बदमाश शोकेस में रखे सोने–चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुवार शाम करीब 6 बजे चार बदमाश हथियारों के साथ ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को धमकाया और दुकान में काम कर रहे राहुल विश्वकर्मा पर गोली चला दी। गोली उसके हाथ में लगी। इसके बाद बदमाशों ने उसके सिर पर बंदूक से वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर अचेत हो गया। घटना से दुकान में मौजूद लोग सहम गए। राहुल के घायल होने के बाद बदमाशों ने दुकान के शोकेस में रखे सोने–चांदी के आभूषणों को समेटना शुरू कर दिया। लूट के बाद चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल राहुल को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घायल कर्मचारी ने इलाज के दौरान पुलिस को बताया कि वारदात में कुल चार लोग शामिल थे। इनमें से एक बदमाश ने नकाब पहन रखा था। बैढ़न में बैंक डकैती की वारदात के बाद जयंत में ज्वेलरी शॉप में हुई इस लूट ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीमें सक्रिय हो गईं। जिले से बाहर जाने वाले रास्तों पर निगरानी बढ़ाते हुए आने–जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। पुलिस टीमों द्वारा ज्वेलरी शॉप और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके साथ ही बदमाशों के भागने के संभावित रास्तों की जानकारी जुटाकर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है।

स्वास्थ्य जागरूकता एवं मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन

प्रयागराज, (संवाददाता)। जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज में एनसीसी एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में लायंस क्लब इलाहाबाद अशोक के सहयोग से आज स्वास्थ्य जागरूकता एवं मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. आशिमा घोष ने अपने स्वागत वक्तव्य से किया। इसके पश्चात उपस्थित मुख्य अतिथियों एवं चिकित्सकों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया तथा स्वस्थ जीवनशैली, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं विभिन्न रोगों से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। चिकित्सकों के परामर्श के पश्चात छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसमें आवश्यक स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिविर में डॉ. आर. के. एस. चौहान नेत्र सर्जन, डॉ. वीरेंद्र डांग अस्थि रोग सर्जन, डॉ. आर. के. सिंह दंत सर्जन, डॉ. मानस तिवारी नेत्र विशेषज्ञ, डॉ. मीतू कपूर स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. श्रेया प्रसाद ईएनटी विशेषज्ञ, डॉ. ए. डी. दुबे फिजिशियन और डॉ. पी. सी. मिश्रा फिजिशियन ने छात्राओं को परामर्श प्रदान किए।

हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत विशिष्ट व्याख्यान एवं समापन समारोह आयोजित

प्रयागराज, (संवाददाता)। राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय मालवीय नगर प्रयागराज में राजभाषा हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज विशिष्ट व्याख्यान एवं समापन समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र सिंह, संयोजक राजभाषा कार्यान्वयन समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी पत्रकारिता पर व्याख्यान रहा। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर अजय प्रकाश खरे सर के मार्गदर्शन में, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र सिंह, संयोजिका नीलिमा सिंह, प्रोफेसर नमिता यादव द्वारा दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती तथा हिंदी सेवी , भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के छायाचित्रों पर माल्यार्पण द्वारा किया गया। मंच संचालिका डॉक्टर वर्षा अग्रवाल के द्वारा मुख्य अतिथि के परिचय द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया।

डंपर चालक गिरफ्तार, कड़ी सुरक्षा में आदित्य का दाह संस्कार

गोरखपुर, (संवाददाता)। गुलरिहा क्षेत्र में डंपर की चपेट में आकर जान गंवाने वाले आदित्य प्रजापति (15) का बृहस्पतिवार दोपहर बरगदही स्थित बैकुंठ धाम पर कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मर्चरी से शव गांव पहुंचने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली थी। पिता राजेश प्रजापति ने बेटे को मुखाग्नि दी। उधर, पुलिस ने चालक श्रवण को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतिम संस्कार स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस की मौजूदगी बनाए रखी गई ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। हादसे के बाद डंपर में आग लगाने और दो अन्य ट्रकों में तोड़फोड़ किए जाने की घटना को भी पुलिस ने जांच के दायरे में लिया है। राहगीरों के मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त करने के आरोपों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी जेपी पाल का कहना है कि पुलिस की ओर से बनाया गया वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जाम के दौरान भीड़ में एक राहगीर के साथ मारपीट और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त किए जाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां भी भांजी थी। इसमें औरंगाबाद निवासी एक युवक ने हाथ में फ्रैक्चर होने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले से संबंधित तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है। इकलौते बेटे आदित्य की मौत के बाद उसकी मां रीनू प्रजापति की हालत लगातार बिगड़ी हुई है। बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान भी वह गहरे सदमे में रहीं। परिजनों के मुताबिक, कुछ देर के अंतराल पर वह बेसुध हो जाती हैं। होश में आने के बाद आदित्य को पुकारते हुए रोने लगती हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि आदित्य घर का इकलौता बेटा था। उसके चले जाने से माता–पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद घर में मातम पसरा है और परिजन रीनू को संभालने में जुटे हैं। आदित्य प्रजापति के निधन की सूचना पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह बृहस्पतिवार को बरगदही स्थित अंत्येष्टि स्थल पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल पिता राजेश प्रजापति सहित परिजन से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया।

घर में मिला वृद्ध का शव, आठ दिन से हो रही थी तलाश, बेटे ने चोरी के दौरान हत्या करने का लगाया आरोप

वाराणसी, (संवाददाता)। जौनपुर जिले में केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेहड़ा गांव में चोरी के दौरान मारपीट में 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या किए

जाने की आशंका से सनसनी फैल गई। 11 सितंबर की रात से लापता विनोद सिंह (70) का शव शुक्रवार को घर के गेस्ट रूम में सड़ी–गली हालत में मिला। कई दिन पुराना शव होने से कमरे से तेज दुर्गंध उठ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। विनोद सिंह सवारी गाड़ी पर खलासी का काम करते थे। परिजनों के मुताबिक, वह मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थ रहते थे। उनका इकलौता बेटा अतुल सिंह लखनऊ में परिवार के साथ रहता है। अतुल के अनुसार, 11 सितंबर की रात से पिता का पता नहीं चल रहा था। उनकी तलाश की जा रही थी। 18 सितंबर को अतुल गांव स्थित घर पहुंचे तो अंदर तेज दुर्गंध महसूस हुई। आसपास के लोगों ने किसी जानवर के मरने की आशंका जताई। इसके बाद घर की सफाई कराई गई। सफाई के दौरान गेस्ट रूम में विनोद का शव पड़ा मिला। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अतुल ने गांव के ही एक युवक और उसके साथियों पर चोरी के दौरान पिता के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपों की जांच शुरू कर दी

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वत्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।